हरोली बल्क ड्रग पार्क: 30 जून 2026 तक की स्थिति

अर्थव्यवस्था / उद्योग / अवसंरचना | समाचार संदर्भ: हिमाचल के हरोली बल्क ड्रग पार्क की प्रगति पर लोकसभा उत्तर, PIB 31 जुलाई 2026 | प्रकाशित: 18 अक्टूबर 2026

पृष्ठभूमि और संदर्भ

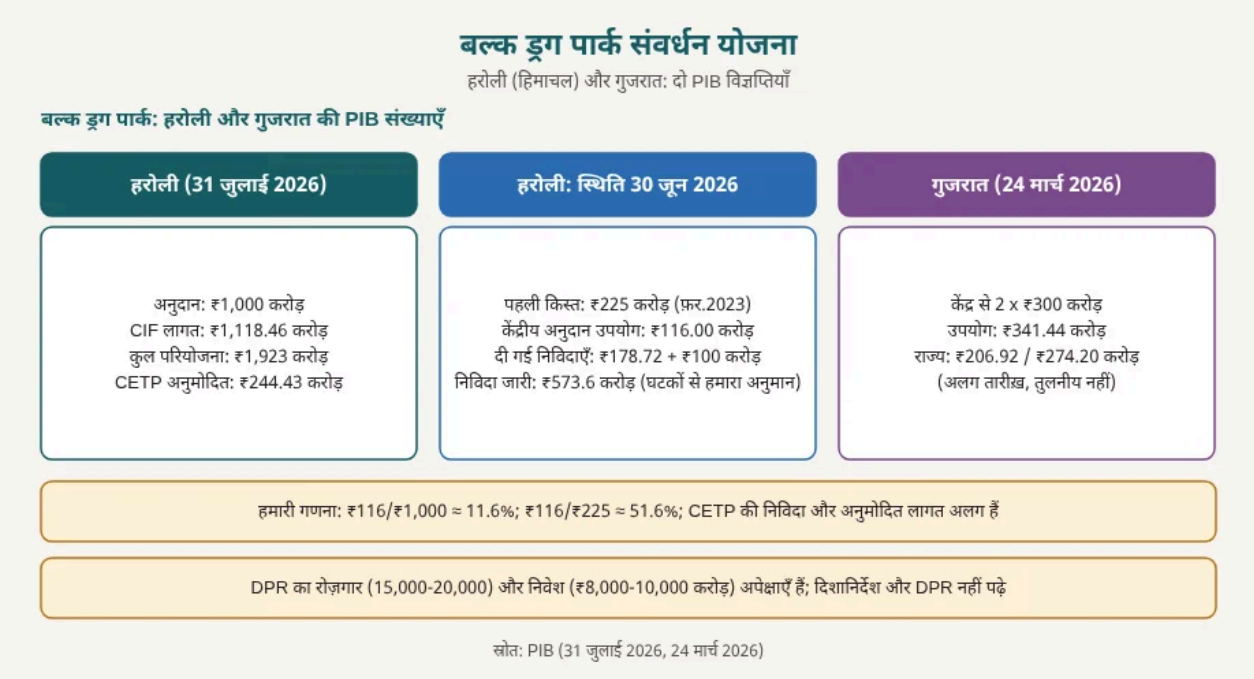
बल्क ड्रग पार्क संवर्धन योजना को मंत्रिमंडल ने 20 मार्च 2020 को मंज़ूरी दी थी। PIB की 24 मार्च 2026 की विज्ञप्ति (गुजरात पर राज्यसभा उत्तर) के अनुसार इसका उद्देश्य तीन बल्क ड्रग पार्क बनाकर साझा बुनियादी सुविधाओं (CIF) से थोक दवाओं की उत्पादन-लागत घटाना है। वित्त वर्ष 2022-23 में आंध्र प्रदेश, गुजरात और हिमाचल प्रदेश में तीन पार्क मंज़ूर हुए। केंद्र की सहायता CIF के लिए प्रति पार्क अधिकतम ₹1,000 करोड़ या परियोजना लागत का 70 प्रतिशत (पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90 प्रतिशत) है, जो भी कम हो।

खबरों में क्यों

PIB की 31 जुलाई 2026 की विज्ञप्ति (लोकसभा में लिखित उत्तर) के अनुसार हिमाचल के ऊना ज़िले के हरोली पार्क के CIF के लिए ₹1,000 करोड़ का अनुदान मंज़ूर है। कुल परियोजना लागत ₹1,923 करोड़ और CIF लागत ₹1,118.46 करोड़ बताई गई है। 30 जून 2026 तक राज्य ने केंद्रीय अनुदान में से ₹116.00 करोड़ और राज्य अनुदान में से ₹0.24 करोड़ CIF पर उपयोग किए।

मुख्य अवधारणा: साझा बुनियादी सुविधाएँ (CIF) और अनुदान की सीमा

CIF का अर्थ है पार्क की साझा सुविधाएँ, जैसे शून्य तरल निस्सारण (ZLD) वाला साझा अपशिष्ट-जल शोधन संयंत्र (CETP), भाप, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और विलायक पुनर्प्राप्ति। PIB के अनुसार योजना के दिशानिर्देशों में सहायता मंज़ूर अनुदान तक सीमित है; हिमाचल ने CETP के लिए अतिरिक्त सहायता का प्रस्ताव भेजा था, और उत्तर में यही दिशानिर्देश-आधारित जवाब दिया गया है। CIF लागत में 70 या 90 प्रतिशत की गणना पार्क-वार होती है, जो हमने दिशानिर्देश खुद पढ़कर जाँची नहीं है।



मौलिक प्रतीकात्मक चित्र: pcsmantra.com

मुख्य तथ्य और आंकड़े

31 जुलाई 2026 (PIB, लोकसभा उत्तर): अनुदान और लागत	**केंद्रीय अनुदान ₹1,000 करोड़; कुल परियोजना ₹1,923 करोड़; CIF ₹1,118.46 करोड़। CETP (ZLD, 5 MLD) की अनुमोदित अनुमानित लागत ₹244.43 करोड़। पहली किस्त ₹225 करोड़, 20 फ़रवरी 2023 को राज्य एजेंसी HPBDPIL को जारी। राज्य ने ₹35.53 करोड़ जारी किए।**
31 जुलाई 2026: प्रगति	पर्यावरण मंज़ूरी 25 सितंबर 2025 को। चरण-1 की सड़क, नाली और पुल की ₹178.72 करोड़ की निविदा दी गई और काम चल रहा है; स्थल-सीमांकन और समतलीकरण की ₹100 करोड़ की निविदा भी दी गई (चरण-1, 800 एकड़)। ZLD सहित CETP (₹273.6 करोड़) और भाप उत्पादन-वितरण (₹300 करोड़) की निविदा जारी हुई है।
31 जुलाई 2026: अपेक्षाएँ (सरकारी दावे)	मंज़ूर DPR के अनुसार प्रत्यक्ष रोज़गार 15,000 से 20,000 और निवेश ₹8,000 से 10,000 करोड़ अपेक्षित। साझा सुविधाओं से पूँजी और संचालन लागत घटने तथा API और मुख्य आरंभिक सामग्री (KSM) के घरेलू उत्पादन में मदद की उम्मीद जताई गई है।
24 मार्च 2026 (PIB, राज्यसभा उत्तर): गुजरात, पहले का सरकारी रिकॉर्ड	केंद्र से ₹300 करोड़ की दो किस्तें मिलीं, जिनमें से ₹341.44 करोड़ उपयोग हुए; राज्य निधि के ₹274.20 करोड़ में से ₹206.92 करोड़। पर्यावरण मंज़ूरी फ़रवरी 2024 में। अधिकांश साझा सिविल काम पूरे बताए गए और CETP जैसी उपयोगिता-निविदाएँ दी जा चुकी हैं।

आँकड़ों की जाँच: जो मेल खाता है और जो स्रोत में अनकहा है

जो मेल खाता है (हमारी गणना): ZLD सहित CETP ₹273.6 करोड़ और भाप ₹300 करोड़ जोड़ने पर ₹573.6 करोड़ बनते हैं, जो विज्ञप्ति की “Rs. 573.6” संख्या से मेल खाता है; विज्ञप्ति में उसके आगे “करोड़” नहीं लिखा, हमने घटकों से इकाई ली है। ₹1,000 करोड़ अनुदान CIF लागत ₹1,118.46 करोड़ का लगभग 89.4 प्रतिशत है। 90 प्रतिशत की सीमा लगाएँ तो CIF का 90 प्रतिशत लगभग ₹1,006.6 करोड़ आता है, यानी ₹1,000 करोड़ की सीमा ही लागू होती दिखती है। यह हमारी गणना है।

जो स्रोत में अलग-अलग दिखता है: CETP की अनुमोदित अनुमानित लागत ₹244.43 करोड़ है, जबकि ZLD सहित CETP की निविदा ₹273.6 करोड़ की बताई गई है। विज्ञप्ति इस अंतर की व्याख्या नहीं करती, और हम उसे हिमाचल के अतिरिक्त सहायता के प्रस्ताव से नहीं जोड़ते। निविदा की राशि में क्या-क्या शामिल है, यह भी हमने नहीं पढ़ा।

हमारी गणना: उपयोग: ₹116.00 करोड़ ₹1,000 करोड़ के अनुदान का लगभग 11.6 प्रतिशत है और जारी हुई एकमात्र बताई गई किस्त ₹225 करोड़ का लगभग 51.6 प्रतिशत। विज्ञप्ति में और किस्तें जारी होने का उल्लेख नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि बाद में कुछ जारी नहीं हुआ। गुजरात के मार्च 2026 के आँकड़ों से हमारी गणना: ₹341.44 करोड़ ₹600 करोड़ का लगभग 56.9 प्रतिशत और राज्य निधि का ₹206.92/₹274.20 लगभग 75.5 प्रतिशत। दोनों राज्यों की स्थितियों की तारीख़ें अलग हैं (30 जून 2026 और 24 मार्च 2026), और गुजरात की कुल CIF लागत हमने नहीं पढ़ी, इसलिए हम इन्हें तुलनीय नहीं मानते।

जो अनकहा है: हरोली में कुल परियोजना ₹1,923 करोड़ और CIF ₹1,118.46 करोड़ का अंतर, यानी लगभग ₹804.54 करोड़ (हमारी घटाव), विज्ञप्ति में समझाया नहीं गया है। निविदा "जारी" होने और "दी गई" होने में फ़र्क़ है; विज्ञप्ति के अनुसार केवल ₹178.72 करोड़ और ₹100 करोड़ की निविदाएँ दी गई हैं।

महत्व: दवा-आपूर्ति, आयात-निर्भरता और पर्यावरण-अनुपालन

आयात-निर्भरता: PIB के अनुसार साझा सुविधाओं से API और KSM का घरेलू उत्पादन बढ़ने और आयात-निर्भरता घटने की उम्मीद है। यह उम्मीद है; उत्पादन या आयात में बदलाव का कोई आँकड़ा इस विज्ञप्ति में नहीं है।

पर्यावरण और ZLD: दवा-उद्योग के अपशिष्ट-जल के लिए ZLD वाला साझा संयंत्र पार्क की केंद्रीय सुविधा है, और पर्यावरण मंज़ूरी 25 सितंबर 2025 को मिली बताई गई है। संयंत्र की निविदा जारी है, दी नहीं गई है, इसलिए संचालन की स्थिति के बारे में हम कुछ नहीं कहते।

केंद्र-राज्य सहभागिता: राज्य ने गैस पाइपलाइन, बहुविध लॉजिस्टिक्स पार्क, NH-44 से सड़क-संपर्क और जैजों (पंजाब) से रेल-विस्तार का मामला संबंधित प्राधिकरणों के साथ उठाया है। NIPER विस्तार केंद्र का कोई प्रस्ताव नहीं है। ये बातें PIB ने राज्य की सूचना के रूप में दी हैं।

चुनौतियाँ और जो हमने नहीं पढ़ा

खर्च की गति और स्रोतों की तारीख़: पहली किस्त फ़रवरी 2023 में जारी हुई और जून 2026 तक ₹116.00 करोड़ का उपयोग बताया गया है। इसके कारण विज्ञप्ति नहीं देती, इसलिए हम कोई कारण नहीं गढ़ते। साथ ही, आँकड़े राज्य सरकार की सूचना पर आधारित हैं।

साझा सुविधाओं के बाहर की ज़रूरतें: अनुदान केवल मंज़ूर राशि तक सीमित है, जबकि सड़क, रेल और गैस जैसी बाहरी कड़ियाँ राज्य के स्तर पर लंबित बताई गई हैं। इनकी समय-सीमा विज्ञप्ति में नहीं है।

जो हमने नहीं पढ़ा: हमने PIB की दोनों विज्ञप्तियाँ पूरी पढ़ीं। योजना के दिशानिर्देश, हरोली की DPR, आंध्र प्रदेश के पार्क की स्थिति, लोकसभा के प्रश्न का पूरा पाठ और 30 जून 2026 के बाद के आँकड़े हमने नहीं पढ़े, इसलिए इन पर हम कोई दावा नहीं करते।

आगे की राह

इसे 30 जून 2026 तक की सरकारी स्थिति की दिनांकित तस्वीर मानें। रोज़गार और निवेश के आँकड़े DPR की अपेक्षाएँ हैं, परिणाम नहीं। गुजरात का रिकॉर्ड पहले की तारीख़ का है, इसलिए दोनों को साथ पढ़ते समय तारीख़ें अलग रखें।

अवधारणा में अंतर

चार बातें अलग रखें: (1) अनुदान की मंज़ूरी, राशि का जारी होना और उसका उपयोग; (2) निविदा जारी होना और दी जाना; (3) DPR की अपेक्षाएँ और वास्तविक परिणाम; (4) PIB की संख्या और हमारी गणना।

मेंस दृष्टि

GS-III: औद्योगिक नीति, अवसंरचना, पर्यावरण; GS-II: केंद्र-राज्य संबंध और सरकारी योजनाएँ।

UPSC CSE Mains शैली: मौलिक अभ्यास प्रश्न

बल्क ड्रग पार्क संवर्धन योजना के उद्देश्य और अनुदान-सीमा को स्पष्ट कीजिए तथा हिमाचल प्रदेश के हरोली पार्क के सरकारी आँकड़ों के आधार पर साझा अवसंरचना परियोजनाओं के क्रियान्वयन की चुनौतियों का मूल्यांकन कीजिए।

(उत्तर 150 शब्दों में दीजिए) | 10 अंक

उत्तर की रूपरेखा

भूमिका में: योजना और तीन पार्क।

मुख्य भाग में: CIF और अनुदान की सीमा; हरोली की लागत, निविदाएँ और उपयोग; अपेक्षाएँ बनाम परिणाम; बाहरी कड़ियाँ और पर्यावरण; आँकड़ों की सीमाएँ।

निष्कर्ष में: साझा अवसंरचना के लिए लागत, निविदा और निधि-उपयोग को चालू सुविधाओं तथा अपेक्षित लाभ से अलग रखें; बाहरी कड़ियों और पर्यावरण की शर्तों सहित हरोली पार्क के क्रियान्वयन को परखें।

स्रोत

- PIB, हिमाचल प्रदेश में बल्क ड्रग पार्क पर लोकसभा में लिखित उत्तर (31 जुलाई 2026)
- PIB, गुजरात में बल्क ड्रग पार्कों की प्रगति पर राज्यसभा में लिखित उत्तर (24 मार्च 2026)

स्रोत: दोनों PIB विज्ञप्तियाँ पूरी पढ़ी गईं। योजना के दिशानिर्देश, हरोली की DPR, आंध्र प्रदेश की स्थिति, प्रश्न का पूरा पाठ और 30 जून 2026 के बाद के आँकड़े नहीं पढ़े गए।

याद रखें: PIB के अनुसार हरोली पार्क के CIF के लिए ₹1,000 करोड़ का अनुदान मंज़ूर है और 30 जून 2026 तक केंद्रीय अनुदान में से ₹116.00 करोड़ का उपयोग हुआ। रोज़गार और निवेश के आँकड़े DPR की अपेक्षाएँ हैं, और निविदा जारी होने तथा दी जाने में अंतर है।